



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2019/वैशाख 12, 1941

No. 135]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2019/VAISAKHA 12, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय – चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के मामले में गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कं. लि. (निर्यातिक) और एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लि. (निर्यातिक) के साथ मै. शैंगडांग ह्वोह्वा टायर कं. लि. (ह्वोह्वा) (उत्पादक) के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अधीन न्यू शिपर समीक्षा।

सं. 7/8/2018-डी जी ए डी.—क. पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) ने चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों (जिसे आगे संबद्ध सामान कहा गया है) के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच दिनांक 3.5.2016 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना सं. 14/14/2015-डी जी ए डी द्वारा शुरू की। प्राधिकारी ने 1.8.2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम द्वारा उपर्युक्त जांच परिणाम में निर्धारित दरों पर चीन से सभी निर्यातिकों/उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और दिनांक 18.09.2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था।
- मै. शैंगडांग ह्वोह्वा टायर कं. लि. (ह्वोह्वा) (उत्पादक) ने गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कं. लि. (निर्यातिक) और एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लि. (निर्यातिक) (जिसे आगे “न्यू शिपर” अथवा आवेदक कहा गया है) दिनांक 18.9.2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए

निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा (एन एस आर) के लिए अनुरोध करते हुए सीमा प्रशुल्क अधिनियम के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र दायर किया।

3. अधिनियम और उसके तहत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्रश्नगत उस निर्यातिक देश में किसी निर्यातिक अथवा उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) करें जिसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की जांचावधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और उस निर्यातिक देश ने किसी भी निर्यातिक और उत्पादक से संबंधित नहीं है जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन रखे गए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि वे चीन अथवा अन्य किसी संबद्ध देश में किसी भी निर्यातिक/उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जिनके विरुद्ध संबंधित उत्पाद के संबंध में पाटनरोधी उपाय लागू हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने मूल जांच की जांचावधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
4. प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत के स्तर पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रथम दृष्टया जांच की है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरूआत का औचित्य पर्याप्त पाया है। प्राधिकारी ने तदनुसार दिनांक 16.05.2018 की अधिसूचना फा. सं. 7/8/2018-डी जी ए डी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत न्यू शिपर समीक्षा शुरू की। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 (6 माह) है। दिनांक 7.6.2018 को प्राधिकारी ने निर्यातिक का नाम एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड ठीक करके एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड रखते हुए शुद्धि पत्र जारी किया।
5. संबद्ध एन एस आर जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 22 के अनुसार यह समीक्षा पूरी होने तक गुआंगज्जोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कं. लि. (निर्यातिक) और एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लि. (निर्यातिक) के साथ मै. शैंगडांग ह्वोहवा दायर कं. लि. (ह्वोहवा) (उत्पादक) द्वारा किए गए संबद्ध सामानों के सभी निर्यातों के संबंध में अनंतिम निर्धारण की सिफारिश की।
6. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25.6.2018 की अधिसूचना सं. 34/2018-सीमाशुल्क (ए डी डी) द्वारा संबद्ध एन एस आर जांच पूरी होने तक आवेदकों द्वारा किए गए संबद्ध सामानों के सभी निर्यातों के संबंध में अनंतिम निर्धारण अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचना में सीमाशुल्क विभाग ने सीमाशुल्क अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शुद्धि पत्र जारी कर दिए जाने के बावजूद निर्यातिक के नाम में संशोधन नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने भी उसके बाद अधिसूचना 34/2018-सीमाशुल्क का शुद्धि पत्र जारी नहीं किया।

ख. प्रक्रिया

7. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है :
 - क. प्राधिकारी ने संबद्ध एन एस आर पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधरण, में प्रकाशित दिनांक 16.05.2018 को सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - ख. प्राधिकारी ने प्रश्नावली की एक प्रति सहित एन एस आर आवेदक को जांच की शुरूआत की प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने जात विचार देने का अवसर दिया।
 - ग. प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत की एक प्रति नई दिल्ली में चीनी दूतावास को भी भेजी।
 - घ. प्राधिकारी ने भारत में जात घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरूआत की एक प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने जात विचार देने का अवसर दिया।
 - ड. जांच की शुरूआत की अधिसूचना के उत्तर में आवेदकों द्वारा निर्यातिक प्रश्नावली के रूप में उत्तर दायर किया गया था।
 - च. जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए और प्रस्तुत तर्कों पर संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उपर्युक्त रूप से विचार किया गया है।
 - छ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए।

- ज. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 13.2.2019 को मौखिक सुनवाई की। हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया था कि वे लिखित अनुरोध भी प्रस्तुत करें तथा उन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों/सूचना के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी गई थी। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- झ. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अन्य सूचना मांगी गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच की गई थी और जहां अपेक्षित था समर्थक दस्तावेज मांगे गए थे।
- ठ. उपर्युक्त नियमावली के नियम 18 के अनुसार प्राधिकारी ने 5 अप्रैल, 2019 को जारी प्रकटन विवरण द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के अनिवार्य तथ्य प्रकट किए और उन्हें सलाह दी कि वे 15 अप्रैल, 2019 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दायर करें। आवेदक और मूल याचिकार्ता से प्राप्त टिप्पणियों को संगत समझी गई सीमा तक वर्तमान जांच परिणाम में हल कर दिया गया है।
- ठ. विवरण में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार मानी गई सूचना दर्शाता है।
- ड. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में उनके गोपनीयता के दावों की जांच की गई है। जो सूचना प्रकृति में गोपनीय है अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अगोपनीय सार सहित जो गोपनीय आधार पर दी गई है, उसे गोपनीय माना गया है।

घरेलू उत्पादकों के विचार

8. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :
- क. यह कि प्राधिकारी समीक्षा के प्रयोजन के लिए पूर्व तारीख पर विचार नहीं कर सकते। यह एच एंड आर जॉनसन मामले में सेस्टेट द्वारा माने गए कानून के विरुद्ध है।
- ख. वर्तमान न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत कानून में बुरी है। नियम 22 की अनिवार्य अपेक्षाएं और पूर्व शर्तें न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत से पूर्व पूरी नहीं की गई हैं। न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत के लिए निर्यातिक और उत्पादक द्वारा दायर किया गया आवेदन पत्र पूर्णतः अपर्याप्त और असिद्ध है।
- ग. आवेदन प्रपत्र व्यापार सूचना का अनुपालन नहीं करता। आवेदक को अद्यतन प्रपत्र के अनुसार आवेदन दायर करना चाहिए था, यहां तक कि यद्यपि, याचिका व्यापार सूचना जारी करने से पूर्व जारी की गई थी। कई ऐसे दस्तावेज/सूचनाएं जिसे निर्यातिक को नए प्रपत्र के अनुसार दायर करना चाहिए था।
- घ. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और कुछ दस्तावेजों के संबंध में गोपनीयता के दावों के लिए कारण देने में विफल रहे हैं तथा इसके भी कोई कारण नहीं दिए गए हैं कि वह सार के लिए संवेदनशील क्यों नहीं है।
- ड. नियम 22 के तहत आवेदक को यह दर्शाना अपेक्षित था कि वह सभी देशों के लिए किसी भी निर्यातिक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जिसके लिए उत्पाद प्रशुल्क लागू था।
- च. आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 की पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया। उपयुक्त एवं पर्याप्त सामग्री न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के लिए नियम 22 के तहत शुरूआत के लिए पूर्व शर्त के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखी गई थी। नियम 22 के तहत यह आवश्यक है कि निर्यातिक देश में आवेदक को जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं करना चाहिए और उस निर्यातिक देश में किसी भी निर्यातिक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं होना चाहिए जो उस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है।
- छ. यह कि चीन से आयातों का पहुंच मूल्य जांच के तहत मूल अवधि से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। अतः घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होती रही।

- ज. यह कि घरेलू उद्योग ने अन्य प्राधिकारियों की परिपाटी सिद्ध करने के लिए विभिन्न देशों की प्रक्रियाएं दी हैं।
- झ. यह कि आवेदकों को निर्यात कीमत सिद्ध करने के लिए वाणिज्यिक मात्राएं निर्यात करनी चाहिए थी।
- ठ. यह कि किसी भी आयातक ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- ठ. यह कि आवेदक से संबंधित पक्षकार वेफांग हुआडोंग रबड़ कंपनी लिमिटेड ने 2010 में दायर अपनी एन एस आर में दावा किया था कि वह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगा हुआ था और भारत को और शेष विश्व को कोई निर्यात बिक्री नहीं की थी। यह संभव नहीं है कि उन्होंने आज की तारीख तक भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
- ड. यह कि आवेदक को मूल जांच में नमूने में शामिल न की गई सहयोगी कंपनियों को दिया गया भारित औसत शुल्क प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त नियम 22 का अभिप्राय यह नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन निर्यातिकों को उनके अपने सामान्य मूल्य और अपनी निर्यात कीमत के आधार पर अलग-अलग पाटन मार्जिन देना अनिवार्य है।

घ. आवेदकों/न्यू शिपर (उत्पादकों एवं निर्यातिकों) के विचार

9. आवेदक के विचारों का सार नीचे दिया गया है :

- क. आवेदक ने मूल जांच की जांचावधि अर्थात् 1.7.2014 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया।
- ख. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्हें बी आई एस लाइसेंस दिसंबर, 2016 में जारी किया गया था और इसीलिए उस अवधि से पूर्व वे भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं कर सकते थे।
- ग. आवेदक कंपनी ने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और ऐसी किसी कंपनी से संबंधित नहीं है जिसने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया हो। आवेदक ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह ऐसे किसी देश में किसी कंपनी से संबंधित नहीं है जिस पर संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लागू हो। इस प्रकार आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 की दोनों अपेक्षाएं पूरी करता है और न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत तथा शुल्क की अलग-अलग दर के निर्धारण के लिए पात्र है।
- घ. आवेदक ने अन्यथिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है। जिन दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा किया गया है उन सब में व्यापारिक गोपनीय सूचना है और वे सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं हैं तथा घरेलू उत्पादकों को प्रभावित नहीं करते अथवा उनका पूर्वाग्रह नहीं है।
- ड. यह कि संबंधित व्यापार सूचना (व्यापार सूचना सं. 08/2018) 25.4.2018 को जारी की गई थी जबकि वर्तमान आवेदन पत्र आवेदक द्वारा उस तारीख से पूर्व दायर किया गया था। इस संबंध में व्यापार सूचना में विशेष रूप से उल्लेख है कि वह उपर्युक्त व्यापार सूचना के जारी होने के “बाद” दायर किए गए आवेदन पत्रों पर लागू है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे का कोई औचित्य नहीं है।
- च. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाए गए मामले से उद्धरण माननीय सेस्टेट की टिप्पणी से संबंधित है जिसे एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य {2008 (232) ई. एल. टी. 390} में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। उच्च न्यायालय ने घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित पैराग्राफ के मामले में सेस्टेट की टिप्पणी पर अपनी नामंजूरी व्यक्त की और नोट किया कि पहली बार के शिपर के मामले में पूर्व की अवधि को नहीं दिया जा सकता। इसके आधार पर उच्च न्यायालय न्यू शिपर समीक्षा के संबंध में उससे सहमत था, जांच की उसी अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए और उसे मना नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क का उपयुक्तता अथवा वैधानिकता के संदर्भ में कोई औचित्य नहीं बनता तथा इसीलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए।

- छ. यह पूर्व शर्त कि निर्यात वाणिज्यिक मात्रा में होने चाहिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के तहत अपेक्षा के विरुद्ध है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में यह उल्लेख है कि प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए न्यू शिपर समीक्षा तब करेंगे यदि (i) उत्पादक अथवा निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात न किया हो और (ii) वह उत्पादक अथवा निर्यातक उस निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित न हो जो उस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हो।
- ज. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार “वाणिज्यिक मात्राओं” की अपेक्षा संबंधित निर्यातकों को पाटनरोधी शुल्क मिलाने के लिए उनकी कीमतें कृत्रिम रूप से कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वस्तुतः उत्तरदाता के लिए उस समय भी निर्यातों की मात्रा अधिकतम करने के लिए अनुचित कीमतों पर संबद्ध सामानों का निर्यात करना अनुचित होगा जब वे घरेलू उद्योग और उन अन्य चीनी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिनके सामानों पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है अथवा बहुत कम लागू है। उत्तरदाता अपनी मानक परिपाटी से विचलित नहीं हुए और जांच की अवधि में ही उसने भारत को निर्यात किया, जब वह बाजार मांग के अनुसार उपयुक्त कीमत प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त चीन से कुल निर्यातों की तुलना एक उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों से करना अनुपयुक्त और कानून के विरुद्ध होगा।
- झ. यह कि वेफांग हुआडोंग रबड़ कंपनी लिमिटेड ने मूल जांच की अवधि के दौरान निर्यात विक्री नहीं की। वेफांग हुआडोंग द्वारा संबद्ध सामानों का यह निर्यात न होना उत्तरदाता के बिन्दु को सिद्ध करता है, कि यदि उन्हें उचित कीमतें प्राप्त नहीं होंगी तो वे किसी बाजार में विक्री नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, उसका आवेदकों के साथ कोई व्यापारिक व्यवहार नहीं है।
- ठ. यह कि प्राधिकारी भारत में सभी मामलों में अपनाए गए अनुसार भारत में उत्पादित संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर उत्तरदाता के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करें।
- ठ. यह कि घरेलू उद्योग के इस अनुरोध कि गैर-नमूना युक्त निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन आवेदकों को दिया जाना चाहिए, का कोई औचित्य नहीं है और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के विरुद्ध है जिसमें न्यू शिपर के लिए शुल्क की अलग दर निर्धारित करने का प्रावधान है। मैक्सिको – राइस में डब्ल्यू ओ पैनल ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 7.159 में यह नोट किया कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 9.4, जिसमें गैर-नमूना युक्त पाटनरोधी शुल्क के लिए प्रावधान है, न्यू शिपर पर लागू नहीं होता। इसके मद्देनजर यह अनुरोध है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 और पाटनरोध समझौता के अनुच्छेद 9.5 के प्रावधान के अनुसार उत्तरदाता को उनके द्वारा किए गए निर्यातों के आधार पर अलग-अलग पाटन मार्जिन दिया जाना चाहिए था। अतः इस संबंध में घरेलू उद्योग का अनुरोध रद्द किए जाने योग्य है।
- इ. **प्राधिकारी द्वारा जांच**
10. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के प्रावधानों, जो निम्नलिखित रूप में पठित हैं, को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर समीक्षा शुरू की।
- “नियम 22**
- (1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, वशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे नियर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

- (2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित नियतिकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 7क की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी।
- बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गरंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा नियतिकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरूआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।"
11. नियम 22 में वे परिस्थितियां निर्धारित हैं जिनके तहत अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए न्यू शिपर समीक्षा जांच की जानी होती है। प्रश्नगत नियतिक देश से किसी भी नियतिक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी की जाएँ :
- (क) यह कि नियतिक अथवा उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का नियत न किया हो।
- (ख) यह कि नियतिक अथवा उत्पादक यह दर्शाएँ कि वह उस नियतिक देश में किसी नियतिक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है, जो संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है।
12. उपर्युक्त से यह सिद्ध है कि नियम 22 के तहत इरादा उस नियतिक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का है जिसने मूल जांच की जांचावधि के दौरान संबद्ध सामानों का नियत नहीं किया। चूंकि उस उत्पादक/नियतिक ने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का नियत नहीं किया, अतः प्राधिकारी मूल जांच के समय उसके नियतों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं कर पाए। अतः न्यू शिपर समीक्षा के प्रावधान का प्रयोजन उस उत्पादक/नियतिक को यह मानते हुए अलग पाटन मार्जिन का दावा करने का अवसर प्रदान करना है कि इन नियतिकों को मूल जांच के दौरान शेष पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया गया है।
13. वर्तमान मामले में आवेदकों ने अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया और न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत का अनुरोध किया। नियम 22 के तहत न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के लिए मूल अपेक्षाएँ यह हैं कि (क) संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है और (ख) जो नियतिक अथवा उत्पादक अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की मांग कर रहे हैं उन्होंने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का नियत न किया हो तथा उन्हें यह दर्शाना चाहिए कि वे उस नियतिक देश में किसी भी नियतिक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं।
14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह समीक्षा एन एस आर जांच के लिए प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु जारी की गई दिनांक 29.01.2019 की व्यापार सूचना 1/2019 के जारी होने से काफी पूर्व शुरू की गई थी। उपर्युक्त व्यापार सूचना में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि वह उपर्युक्त व्यापार सूचना के जारी होने की तारीख के बाद दायर किए गए एन एस आर आवेदन पत्रों पर लागू है। अतः यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त व्यापार सूचना में निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रक्रिया को व्यापार सूचना 1/2019 से पूर्व दायर किए गए एन एस आर आवेदन पत्रों पर लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने न्यू शिपर समीक्षा आवेदन पत्र दायर करने से पूर्व विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू किया था।
15. न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत से पूर्व प्राधिकारी को स्वयं को प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट करना अपेक्षित है कि नियम 22 की शर्तें पूरी की जाएँ। जब तक आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों का विरोध करने के लिए वास्तविक प्रतिकूल साध्य नहीं हैं तब तक न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत से इन्कार नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत की तारीख को यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं थी कि एन एस आर आवेदन द्वारा दिए गए विवरण सही नहीं थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत करने से पूर्व प्रधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं थे।
16. न्यू शिपर के रूप में आवेदक की पात्रता की जांच करने के लिए आवेदक से कहा गया था कि क्या (क) कंपनी ने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का नियत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किया था और (ख) आवेदक अथवा उसकी किसी संबंधित कंपनी ने मूल जांच की जांचावधि में भारत को संबंधित उत्पाद का नियत किया था।

आवेदक ने यह उल्लेख करते हुए प्रमाणन प्रदान किया है कि :

- क. आवेदक ने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिसंबर, 2016 में ही अर्थात् मूल जांचावधि समाप्त होने के बाद निर्यात करने के लिए बी आई एस लाइसेंस प्राप्त किया।
 - ख. आवेदक चीन में किसी भी निर्यातिक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है जिसने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया हो।
 - ग. आवेदक की संबद्ध कंपनियां संबद्ध सामानों के विनिर्माण में नहीं लगी थीं।
 - घ. आवेदक की संबद्ध कंपनियां चीन में किसी भी निर्यातिक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं हैं जिन्होंने मूल जांच की जांचावधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया हो।
17. प्राधिकारी ने इस संबंध में घेरेलू उत्पादकों के अनुरोधों पर विचार किया परंतु न्यू शिपर होने के आवेदक के दावे के विरुद्ध कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं पाई।
18. जांच के दौरान प्राधिकारी ने चीन में किसी निर्यातिक अथवा उत्पादक के साथ आवेदक के संबंध के बारे में न तो कोई साक्ष्य पाया जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है और न ही इस संबंध में कोई वास्तविक साक्ष्य किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष लाया गया। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि न्यू शिपर समीक्षा जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई थी जो डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुरूप है।
19. जहां तक जांच की अवधि का संबंध है, प्राधिकारी 12 माह से कम परंतु 6 माह से अधिक की अवधि निर्धारित करने के लिए अपने अधिकारों के अंतर्गत हैं। न्यू शिपर के मामले में जांच की अवधि के रूप में कम समयावधि पर विचार करना असामान्य नहीं है। इस प्रकार, जांच की अवधि का चयन औचित्यपूर्ण है।
20. प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के आवेदक के प्रयास में राजस्व विभाग में अधिसूचना में निर्यातिक का नाम सही करने के संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित न किए जाने के कारण बाधा आई थी।
21. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नलिखित है:
- "गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"
22. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक समझा गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितवद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई

सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण की पद्धति

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत संबंधी अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. यह कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
- ii. यह कि चूंकि आवेदकों ने अतिरिक्त प्रश्नावली दायर नहीं की है और इसीलिए वे उनके अपने आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य के लिए हकदार नहीं हैं।
- iii. सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्धारित प्रपत्र में अपनाए गए सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आवेदक निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह चाहते हैं कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की उपेक्षा कर सामान्य मूल्य निर्धारित करें।
- iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य का आधार निम्नलिखित है :
 1. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर
 2. भारत सहित अन्य देशों में इस तीसरे देश से कीमत
 3. कोई अन्य उपयुक्त आधार जिसमें उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समान उत्पाद के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित भारत में वास्तविक रूप से भुगतान अथवा देय कीमत शामिल हो।
- v. इसके अतिरिक्त नियम 22 का अभिप्राय यह नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इन निर्यातकों को उनके अपने सामान्य मूल्य और अपनी निर्यात कीमत के आधार पर अलग पाटन मार्जिन देना अनिवार्य है।

एन एस आर आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

24. यह कि प्राधिकारी को अपनी मानक परिपाठी के अनुसार उनके लिए सामान्य मूल्य निर्मित करना चाहिए।
25. यह कि प्राधिकारी को उत्पादक एवं निर्यातक की निर्यात मात्राओं के आधार पर निर्यात कीमत का प्रयोग करना चाहिए। यह भी अनुरोध है कि चूंकि एक निर्यातक के नाम ने सीमाशुल्क अधिसूचना में संशोधन नहीं किया गया था अतः सरकार के दो विभागों के बीच आपसी समझ के अभाव के कारण आवेदकों के विरुद्ध प्रतिकूल विचार नहीं रखा जा सकता।

प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं चाइना एसेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है :

"गैट 1994 का अनुच्छेद VI, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार ('पाटनरोधी करार') तथा एससीएम करार उन कार्यवाहियों में लागू होगा जिनमें डब्ल्यूटीओ सदस्य में चाइनीज मूल का आयात निम्नलिखित से संगत हो:

(क) गैट 1944 के अनुच्छेद VI तथा पाटन रोधी करार के अंतर्गत तुलनीयता कीमत निर्धारित करने में आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य जांचाधीन उद्योग अथवा किसी पद्धति के लिए चीनी कीमत अथवा लागतों का प्रयोग करेगा जो निम्नलिखित नियमावली पर आधारित चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना हेतु आधारित नहीं है।

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि विनिर्माण उत्पादन और उस उत्पाद की बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति उपलब्ध है, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता निर्धारित करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा;
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का प्रयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित नहीं है यदि जांचाधीन उत्पाद स्पष्ट रूप से नहीं दर्शि सकता है कि उक्त उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद उत्पादित करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था परिस्थितियां विद्यमान हैं।
- (ख) जब अनुच्छेद 14(क), 14 (ख), 14 (ग) और 14(घ) में उल्लिखित समिक्षा का पता लगाने के लिए एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में एससीएम करार के संबंधित प्रावधान लागू होंगे। यदि उस आवेदन में विशेष कठिनाइयां हैं तो आयात डब्ल्यूटीओ सदस्य समिक्षा लाभ जो उस संभावना जो चीन में विद्यमान निवंधन एवं शर्तों हैं, को ध्यान में रखते हुए समिक्षा के लाभ अभिचिन्हित करने और मापने के लिए पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उपयुक्त बैनर्मार्क के लिए सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार की पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक सदस्यों को चीन से बाहर विद्यमान निवंधन एवं शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पूर्व प्रचलित इस प्रकार की निवंधन एवं शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य पाटनरोधी प्रक्रियाओं संबंधी समिति के लिए उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयोग की कई पद्धतियां अधिसूचित करेंगे तथा समिक्षा और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति के लिए उप-पैरा (ख) के अनुसार पद्धतियां अधिसूचित करेंगे।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक बार चीन में प्रमाणित हो जाता है और यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है तो पैराग्राफ (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य का राष्ट्रीय कानून अभिवृद्धि की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था मानदण्डों से युक्त हो। किसी भी स्थिति में उप-पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान की अभिवृद्धि की तारीख के 15 वर्ष पश्चात समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त चीनी आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह प्रमाणित करेगा कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां उपलब्ध हैं तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए अब लागू नहीं होंगे।
27. अनुच्छेद 15 का अभिप्राय यह है कि उप-पैरा (क) (ii) के प्रावधान चीनी अभिगम की तारीख से 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इस पैराग्राफ के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए।
28. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ के साथ हस्ताक्षरित अभिगम नयाचार के पैरा 15 (क) (i) के तहत प्रतिबद्धताओं में यह अपेक्षित है कि जांचाधीन उत्पादकों को यह स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था बाली स्थितियां उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विद्यमान हैं। यह सिद्ध हो जाने की स्थिति में आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनात्मकता निर्धारित करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 और भारत की पाटनरोधी नियमावली में यह अपेक्षित है कि उत्पादक/निर्यातक के वित्तीय रिकॉर्ड उपयुक्त रूप से उत्पादन लागतें दर्शाएं। अतः निम्नलिखित के संबंध में उसकी सूचना और समर्थक साक्ष्य दिया जाना अपेक्षित है।
- क. कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश सहित कीमत, लागत, इनपुट के संबंध में निर्णय मांग और आपूर्ति दर्शने वाले बाजार संकेत तथा बिना किसी महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप और क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती है, के अनुरूप लिए जाते हैं।

- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी ह्लास से प्रभावित नहीं होती।
- ग. उत्पादक/नियर्तिक दिवालियापन तथा संपत्ति कानून के अध्यधीन होते हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी सुनिश्चितता और स्थिरता की गारंटी देता है।
- घ. विनिमय दर परिवर्तन बाजार दरों पर किए जाते हैं।
29. इस जांच में कार्रवाई के भाग के रूप में प्राधिकारी ने उपर्युक्त सूचना मांगते हुए आवेदक को पूरक प्रश्नावली भेजी थी। उपर्युक्त पूरक प्रश्नावली का आवेदक से कोई उत्तर न आने के कारण प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है।
30. निर्धारित किया गया निर्मित सामान्य मूल्य *** अम. डॉ. प्रति मी.ट. है।

नियाति कीमत

31. नियातिक प्रश्नावली के अनुसार जांच की अवधि के दौरान आवेदक ने भारत में स्वतंत्र ग्राहकों को सीधे ही *** अम. डॉ. निवल बीजक मूल्य के लिए भारत को संबद्ध सामानों का *** मी.ट. (*** टायर) का नियाति किया। आवेदक ने अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा, पत्तन सार संभाल व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी है और आवेदक के संबंध में कारखानागत स्तर पर नियाति कीमत निर्धारित की है। इसके ब्यौरे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित हैं।

पाटन मार्जिन

32. उपर्युक्त निर्धारित नियाति कीमत और सामान्य मूल्य की तुलना करते हुए जांच की अवधि के दौरान आवेदक के लिए निर्धारित अलग पाटन मार्जिन निम्नलिखित है:-

सामान्य मूल्य	अम.डॉ./मी.ट.	***
नियाति कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मर्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मर्जिन	%	***
पाटन मर्जिन	रेंज	0-10

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

i. प्राधिकारी ने पूरक पश्नावली जारी की है और उसके संबंध में असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अश्चर्य की बात यह है कि नियातिक ने यह भी दावा किया है कि सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिकलित किया जाए। यह प्रकट नहीं किया गया है कि किन उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया गया है। नियातिक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 0-10 प्रतिशत है जो बहुत कम है और इस प्रकार यदि पाटनराठी शुल्क निर्धारित करने के लिए उस पर विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग के प्रति काफी पूर्वाग्रह होने की संभावना है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग सामान्य मूल्य के संबंध में टिप्पणियां देने में असमर्थ है।

ii. संबद्ध पक्षकार की मौजूदगी के संबंध में मौखिक सुनवाई और उसके बाद लिखित अनुरोध में विशेष अनुरोधों के बावजूद उन पर विचार नहीं किया गया है और प्रकटन विवरण में भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जब घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से कुछ कंपनियों की पहचान की है तो प्रकटन विवरण में यह उल्लेख नहीं है कि क्या वे कंपनियां आवेदक से संबद्ध हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करें और उसके बाद अनिवार्य तथ्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को जारी करें तथा सूचित करें भले ही कोई अन्य संबद्ध पक्षकार हो अथवा नहीं तथा उन्होंने भारत को सामानों का नियाति किया हो अथवा नहीं।

- iii. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्राधिकारी का व्यापार चैनल पृथक शुल्क, यदि लगाए गए, एच के ट्रेड विंड लिमिटेड को प्रदान करने पर विचार करने प्रस्ताव है।
- iv. मौखिक सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया था कि सामान्य मूल्य निर्यातक की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाए। पूरक प्रश्नावली जारी की गई थी, तथापि निर्यातक ने अपने को उसका उत्तर देने से अलग रखा। इस प्रकार निर्यातक को असहयोगी निर्यातक माना जाना चाहिए और जांच तत्काल रद्द की जानी चाहिए।
- v. प्रकटन विवरण में नोट किए गए अनुसार एन एस आर आवेदक द्वारा किए गए प्रत्युत्तर अनुरोधों पर घरेलू उद्योग का उत्तर निम्नलिखित है :
- क. आवेदकों ने अनुरोध किया था कि उन्हें वी आई एस लाइसेंस दिसंबर, 16 में जारी किया गया था और इसीलिए उस अवधि से पूर्व वे भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं कर सकते थे। घरेलू उद्योग पाटनरोधी कार्रवाई पर ऐसे विवरण की संगतता और महत्वा समझने में असमर्थ है। तथापि आवेदक ने उपर्युक्त वी आई एस लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी निर्यात नहीं किया है।
- ख. आवेदक ने उल्लेख किया कि उसने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया। घरेलू उद्योग ने आवेदक द्वारा दावा किए गए गोपनीय दस्तावेजों की पूर्ण सूची उपलब्ध कराई है जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। उससे घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाया।
- ग. जहां तक इस आवेदक द्वारा इस तर्क का संबंध है कि व्यापार सूचना संख्या 08/2018 वर्तमान आवेदन करने के बाद जारी की गई थी और इस प्रकार लागू नहीं है, घरेलू उद्योग यह उल्लेख करता है कि यदि आवेदन पत्र पूर्व में भी जारी किया गया था तो आवेदन पत्र को अद्यतन करने का पर्याप्त समय था और यदि व्यापार सूचना आवेदन पत्र के बाद की थी तो व्यापार सूचना के सिद्धांत फिर भी लागू होते हैं।
- घ. घरेलू उद्योग का दावा है कि एन एस आर आवेदक एच एंड आर जानसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य {2008 (232) ई एल टी 390} में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के संबंध में अपूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर प्राधिकारी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। संदर्भ में दिया जा रहा उच्च न्यायालय का आदेश एक अंतरिम राहत आदेश है जिसमें न्यायालय ने अधिकरण के आदेश के औचित्य पर ध्यान नहीं दिया। सेंट गोबाइन बनाम भारत संघ की रिट अपील सं. 2018 का 412 से 414 (सबसे हाल का मामला) में मद्रास उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि एच एंड आर जानसन ने अधिकरण की जांच परिणाम सही हैं क्योंकि उस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका वापस ली गई थी।
- ड. आवेदक निर्यातक ने वर्तमान जांच को दायर करने से पूर्व उत्पादन शुरू किया था। इस प्रकार, पूर्व की जांच अवधि पर विचार करना और भी संगत है। इसके अतिरिक्त यह स्वीकार भी किया जाए कि जांच की प्रभावी तारीख प्रथम बार के शिपर दी जाए तो किए जाने वाले लेनदेनों की अधिकृतता की जांच करने के लिए यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मामले में जांच की प्रभावी अवधि प्राप्त करने के बाद आवेदक ने पूरी जांच की अवधि के दौरान केवल एक माल का निर्यात किया है जो आवेदक की दुर्भावना दर्शाता है।
- च. आवेदक यह दर्शनि में विफल रहा है कि वाणिज्यिक मात्रा की आवश्यकता पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के उल्लंघन में कैसे है। वाणिज्यिक मात्राओं की अपेक्षा कई डब्ल्यू टी औ सदस्यों द्वारा ली गई है। डी जी टी आर में भी 25 अप्रैल 2018 की व्यापार सूचना सं. 08/2018 के माध्यम से न्यू शिपर समीक्षा के भाग के रूप में वाणिज्यिक मात्राएं शामिल की हैं। अन्य न्याय व्यवस्थाओं द्वारा एन एस आर आवेदन पत्रों में भारतीय विगत परिपाटी और न्याय व्यवस्था भी यह दर्शाती है कि न्यू शिपर द्वारा निर्यात लेनदेनों को “वाणिज्यिक/काफी मात्रा” होना चाहिए।
- छ. एन एस आर आवेदक ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित “वाणिज्यिक मात्राओं” की अपेक्षा पाटनरोधी शुल्क को मिलाने के लिए संबंधित नियर्यातकों को उनकी कीमतें कृत्रिम रूप से कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एन एस आर आवेदक की यह अवधारणा वास्तविकता में किसी आधार से परे है। जैसा कि वर्तमान मामले में देखा जा सकता है आवेदक की कीमतें उन कीमतों से कृत्रिम रूप से अधिक हैं जिन पर वही शुल्क लगने वाले अन्य उत्पादक

वसूली करने में सक्षम हैं। दूसरे, इस तर्क का अपने आप में यह अर्थ है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यू शिपर समीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि नियातिक वाणिज्यिक मात्राओं में नियात नहीं कर सकते और निर्दिष्ट प्राधिकारी वाणिज्यिक मात्राओं में नियात के बिना नियात कीमतें निर्धारित नहीं कर सकते। वाणिज्यिक मात्राओं को उत्पाद की प्रकृति के आलोक में देखा जाना होता है। यह एक मुद्दा है कि क्या केवल 260 पीस 60-80 लाख पीसों के क्षेत्र में मांग वाले उत्पाद में वाणिज्यिक मात्रा हैं और क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी इतने कम आयातों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं। तीसरे, जब इतने अधिक नियातिकों ने शुल्क सहित इतनी अधिक मात्राओं का नियात किया है (उनमें से कई पर शेष शुल्क लग रहा है), तो क्या नियातिक नियात करने में शुल्क की मौजूदगी एक बाधा होने का दावा कर सकते हैं। चौथे, जब पाटनरोधी शुल्क प्रदत्त कीमतें घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम हैं तो पाटनरोधी शुल्क के बाद भी उपर्युक्त मात्रा में विक्री करने में नियातिक को कौन रोक रहा है। इस प्रकार यह अस्पष्ट रहा है कि क्यों और कैसे एन एस आर आवेदक ने अन्य चीनी कीमतों से अधिक कीमत पर वाणिज्यिक नियात किए हैं तथा भारत में किसी ग्राहक ने अन्य चीनी आपूर्तिकर्ताओं से खरीददारी करने के बजाए इतनी अधिक कीमत पर कैसे खरीददारी की।

- ज. एन एस आर आवेदक ने गैर-नमूनाकृत सहयोगी नियातिकों को उपलब्ध दर अपनाने के बजाए शुल्क की अलग दर प्रदान किए जाने के लिए तर्क देते समय मैक्सिको-राइस मामले डब्ल्यू टी ओ पैनल की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। मैक्सिको-राइस में टी ओ पैनल की रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का तर्क गलत रखा गया है क्योंकि उस पैनल की रिपोर्ट में जांच में नमूनाकरण भी नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में केवल यह दिया गया है कि करार के अनुच्छेद 9.5 में किसी आर-पार के संवर्ग का अभाव यह दर्शाता है कि प्राधिकारी पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वह अनुच्छेद 9.4 के अनुसार निष्क्रिय मार्जिन देकर शेष शुल्क मार्जिन का परिकलन करे। डब्ल्यू टी ओ पैनल की टिप्पणी कानून के तहत प्राधिकारी पर दायित्व के संबंध में और वह भी मूल जांच में थी।

एन एस आर आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

33. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चूंकि प्राधिकारी ने गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (नियातिक) और एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड (नियातिक) के साथ मै. शानडोंग हवोहवा टायर कंपनी लिमिटेड (हवोहवा) की श्रृंखला के लिए जांच शुरू की थी और सीमाशुल्क में केवल उपर्युक्त श्रृंखला के लिए पाटनरोधी शुल्क के भुगतान की अनंतिम रूप से छूट दी है, अधिसूचना में इस श्रृंखला का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि अनंतिम मूल्यांकन को भी तदनुसार अंतिम रूप दिया जा सके। आवेदक का अनुरोध है कि उस श्रृंखला को अंतिम यांत्रिक परिणाम में भी उल्लिखित किया जाए।

ज. प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा अधिकतर अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं और वर्तमान जांच परिणाम के पूर्व भागों में तथा प्रकटन विवरण जारी करने के समय उनकी जांच की गई है तथा हल किए गए हैं। उपर्युक्त जांच परिणाम घरेलू उद्योग एन एस आर आवेदक के उन सभी तर्कों पर कार्रवाई करते हैं। तथापि, प्राधिकारी ने संगत मानी गई सीमा तक और अन्यत्र हल न किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की है।

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि राजस्व विभाग द्वारा शुद्धि पत्र जारी न किए जाने के बावजूद उत्पादक मै. शानडोंग हवोहवा टायर कंपनी लिमिटेड को दूसरे नियातिक मै. गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से उपर्युक्त मात्रा में संबद्ध सामानों का नियात करने का विकल्प था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य उन्होंने इस व्यापारी के माध्यम से *** मीट. की बहुत ही कम मात्रा का नियात करने का विकल्प चुना है, अधिकृतता के संबंध में प्रश्न उठाता है।

- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने पूरी जांच की अवधि के दौरान भारत को बहुत कम संबद्ध सामानों का नियात किया है। नियात की इतनी कम मात्रा को उपर्युक्त मात्रा नहीं माना जा सकता और ऐसे नियात लेन-देन अलग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखे जाने के लिए काफी प्रतिनिधिकारक नहीं हैं।

ज. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

35. तदनुसार, प्राधिकारी एन एस आर आवेदक अर्थात् मै. शानडोंग हाओहुआ टायर कं. लि. (हाओहुआ) (उत्पादक),

गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी कं. लि. (निर्यातक) और एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड (निर्यातक) के साथ के लिए कोई अलग पाटन मार्जिन की सिफारिश नहीं करते।

36. प्राधिकारी मानते हैं कि एन एस आर आवेदक अलग पाटन मार्जिन के हकदार नहीं हैं। अतः प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि वर्तमान एन एस आर जांच की शुरूआत की तारीख से मै. शानडोंग हाओहुआ टायर कं. लि. (हाओहुआ) (उत्पादक), मै. गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी कं. लि. (निर्यातक) और मै. एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड (निर्यातक) को 18.9.2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क (ए डी डी) द्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से नियांति संबद्ध सामानों के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाए।

ट. आगे की प्रक्रिया

37. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार और मै. जिंदल पोलीफिल्म लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 8202/2017 में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: **New Shipper Review under Rule 22 of the Anti-Dumping Rules for determination of individual dumping margin for M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. (Haohua) (Producer) with Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., (exporter) and H K Trade Wind Trading Limited (exporter) in the case of anti-dumping duty imposed on New/unused Pneumatic Radial Tyres originating in or exported from China PR**

F. No. 7/8/2018-DGAD —A. BACKGROUND

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") initiated anti-dumping duty investigation concerning "New/unused Pneumatic Radial Tyres" (hereinafter referred to as "subject goods") originating in or exported from China vide initiation Notification No F.No.14/14/2015-DGAD dated 3.5.2016. The Authority vide final findings dated 1.8.2017 recommended an anti-dumping duty for all exporters/producers from China at the rates prescribed in the said findings. The recommendation of the Designated Authority was accepted by the Central Government and antidumping duty was levied vide Customs Notification No. 45/2017- Customs (ADD) dated 18.9.2017.
2. M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. (Haohua) (Producer) with Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., (exporter) and H K Trade Wind Trading Limited (exporter) (hereinafter referred to as "New Shippers" or "Applicants") filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with Rule 22 of the AD Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) in respect of the definitive anti-dumping duty imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 45/2017- Customs (ADD) dated 18.9.2017, concerning imports of the subject goods, originating in or exported from China.
3. The Act and the AD Rules made thereunder require the Authority to undertake a New Shipper Review (NSR) for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country and is not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to the antidumping duty. The applicant has claimed that they are not related to any of the exporters/producers in China or other subject countries against whom anti-dumping measures are in force with regard to the product concerned. Furthermore, they have claimed that they have not exported the product concerned during the period of investigation of the original investigation.

4. The Authority prima facie examined the information submitted by the applicant at the stage of initiation of the investigation and found it adequate to justify the initiation of a new shipper review investigation in accordance with the provisions of Rule 22 of the AD Rules. The Authority accordingly initiated the New Shipper Review under Rule 22 of the AD Rules vide Notification F. No. 7/8/2018-DGAD dated 16.5.2018. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st July 2018 to 31st December 2018 (6 months). On 7.6.2018, the Authority issued corrigendum correcting the name of exporter from H K Trade Wing Trading Limited to H K Trade Wind Trading Limited.
5. Having initiated the subject NSR investigation, the Authority recommended provisional assessment on all exports of subject goods made by M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. (Haohua) (Producer) with Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., (exporter) and H K Trade Wind Trading Limited (exporter), till this review is completed in accordance with Rule 22 of the Rules supra.
6. Ministry of Finance notified the provisional assessment on all exports of the subject goods made by applicants till completion of the subject NSR investigation vide Notification No. 34/2018- Customs (ADD) dated 25.6.2018. In the said notification the customs have not amended the name of the exporter despite the corrigendum having been issued by the Designated Authority prior to the issuance of the Custom Notification. The Ministry of Finance did not even issue corrigendum of notification 34/2018-customs subsequently.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - a. The Authority issued a public notice dated 16.5.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
 - b. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the NSR applicant along with a copy of the questionnaire and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - c. The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the Chinese Embassy at New Delhi.
 - d. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - e. In response to the initiation notification, response in the form of Exporters Questionnaire was filed by applicants.
 - f. Arguments raised and submitted by various interested parties during the course of the investigation, to the extent considered relevant have been appropriately considered by the Authority in this final findings.
 - g. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
 - h. The Authority held Oral Hearings on 13.2.2019 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). The interested parties were asked to furnish written submission as well and were also allowed to submit rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from are interested parties appropriately.
 - i. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. The data submitted by the Applicant was examined and back-up documents were called for, wherever required.
 - j. In accordance with Rule 18 of the Rules supra, the Authority disclosed the essential facts of the present investigation to all interested parties vide a disclosure statement issued on 5th April , 2019, and advised them to file the comments on the disclosure statement by 15th April, 2019. The comments received from the applicant and the original petitioner, have been addressed in the present findings to the extent considered relevant.
 - k. *** in the statement represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the AD Rules.
 - l. The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a

confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated confidential.

C. Views of the Domestic Producers

8. The submissions made by the Domestic Industry and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. That the Authority cannot consider prospective period for the purpose of review. This is contrary to the law upheld by CESTAT in H& R Johnson case.
 - b. The initiation of the present New Shipper Review is bad in law. The mandatory requirements and pre-conditions of Rule 22 have not been satisfied prior to initiation of new shipper review. The application filed by the exporter and the producer for the initiation of new shipper review is grossly inadequate and unsubstantiated.
 - c. Application format does not adhere to the trade notice. Applicant should have filed application as per updated proforma even though petition was filed before the issuance of the trade notice. There are certain documents/ information that the exporter should have filed as per the new format.
 - d. The Applicant has claimed excessive confidentiality and failed to provide reasons for claims of confidentiality on certain documents and no reasons have also been provided as why the same is not susceptible to summarization.
 - e. Under Rule 22, the Applicant was required to show that it is not related to *any* exporter or producer ‘for all the countries for which duty on the product was applicable’.
 - f. The Applicant did not fulfill the pre-conditions of Rule 22 of the AD Rules. Appropriate and sufficient materials were not placed before the Designated Authority as a pre-condition for initiation under Rule 22 to initiate new shipper review. It is necessary under Rule 22 that the Applicant in the exporting country must not have exported the subject goods to India during the period of investigation and should not be related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.
 - g. That the landed value of the imports from China is below the selling price of the Domestic Industry since original period under investigation. Therefore, Domestic Industry continued to suffer injury.
 - h. That the Domestic Industry has provided procedures of different countries to establish the practice of other authorities.
 - i. That the applicants should have exported commercial quantities to establish export price.
 - j. That none of the importers have filed any importers questionnaire response.
 - k. That Weifang Huadong Rubber Co. Ltd, related party to the applicant, had claimed in its NSR filed in 2010 that it was involved in the production of PUC and had not made any export sales to India and the rest of the world. It is not possible that they have not exported PUC to India till date.
 - l. That the Applicant may be granted the weighted average duties given to cooperating companies not included in the sample in the original investigation. Further, Rule 22, does not imply that the Designated Authority is obliged to give individual dumping margin to these exporters on the basis of their own normal value and own export price.

D. Views of the Applicants / New Shipper (Producer cum Exporter)

9. The views of the Applicant have been summarized below:
 - a. The Applicant did not export the PUC to India during the period of investigation of the original investigation, i.e., 1.7.2014 to 31.12.2015.
 - b. The Applicants has submitted that the BIS license was issued to them in December 2016, and therefore, before that period they could not have exported the subject goods to India.
 - c. The Applicant Company has not exported PUC to India during the period of investigation of the original investigation and is not related to any other entity that had exported PUC to India during the period of investigation of the original investigation. The Applicant also certified that it is not related to any entity in any country on which anti-dumping duty on the subject goods is applicable. Thus, the Applicant satisfied both the requirements of Rule 22 of the AD Rules and was eligible for the initiation of the New Shipper Review and the determination of an individual rate of duty.

- d. The Applicant did not claim excessive confidentiality. All the documents upon which confidentiality was claimed contain business confidential information and are not available in the public domain and did not impact or prejudice the Domestic Producers.
- e. That the concerned trade notice (Trade Notice No. 08/2018) was issued on 25.04.2018, while the present application was filed by the applicant prior to that date. In this regard, the trade notice specifically mentions that it is applicable on the applications filed ‘after’ the issuance of said trade notice. Therefore, there is no merit in the issue raised by the Domestic Industry.
- f. That the excerpt from case cited by the domestic industry refers to an observation of the Hon’ble CESTAT which was struck down by the Hon’ble High Court of Delhi in H and R Johnson (India) Limited v. Union of India & Ors. [2008 (232) E.L.T. 390]. The High Court expressed its disapproval on observation of the CESTAT in the paragraph cited by the domestic industry and noted that in the case of a first-time shipper, a retrospective period cannot be taken. Based on this, the High Court agreed that, with respect to New Shipper Review, a prospective period of investigation must be allowed and cannot be ruled out. In view thereof, the contention of the Domestic Industry in this regard holds no merit in terms of their reasonability or legality, and therefore, should be rejected.
- g. The pre-condition that exports should be in commercial quantum is contrary to the requirement under Rule 22 of the Anti-dumping Rules and Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement. Rule 22 of the Anti-dumping Rules states that the Authority shall carry out new shipper review to determine individual margin of dumping if (i) the producer or exporter has not exported the product to India during the period of investigation and (ii) this producer or exporter is not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.
- h. That the requirement of “commercial quantities” as proposed by the Domestic Industry shall encourage the concerned exporters to artificially lower down their prices to absorb the anti-dumping duties. In fact, it would be untenable for the respondent to export the subject goods at unfavourable prices in order to maximize quantity of exports even when they are competing against the prices offered by the Domestic Industry and other Chinese producers on whose goods there is no or lesser anti-dumping duties applicable. The respondent did not deviate from its standard practice and exported to India during the POI only when it was able to obtain suitable price in accordance with market demand. Further, to compare total exports from China to exports made by one producer would be unreasonable and contrary to law.
- i. That M/s Weifang Huadong Rubber Co., Ltd did not make export sales during the original POI. This non-export of subject goods by Weifang Huadong proves the point of the respondent, that if they will not get the fair prices, they will not sell to any market. Moreover, it does not have any business dealings with the applicants.
- j. That the Authority may determine the normal value for the respondent on the basis of the cost of production of the subject goods produced in India, as followed in all the cases in India.
- k. That the submission of the Domestic Industry that dumping margin for non-sampled exporters should be awarded to applicants is without any merit and contrary to the Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement which provides for determination of individual rate of duty for a new shipper. The WTO panel in Mexico –Rice, in para 7.159 of its report noted that Article 9.4 of the Anti-Dumping Agreement, which provides for non-sampled anti-dumping duty rate does not apply to new shipper. In view thereof, it is submitted that in terms of the provision under Rule 22 of the Anti-dumping Rules and Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement, the respondent ought to be given an individual dumping margin on the basis of the exports made by them. Therefore, the submission of the Domestic Industry in this regard is liable to be rejected.

E. Examination by the Authority

10. The Authority initiated the New Shipper Review keeping in view the provisions of Rule 22 of the AD Rules, which reads as follows:

“Rule 22

(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the

exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of initiation of the review”.

11. Rule 22 specifies the circumstances under which a New Shipper Review investigation is to be carried out for the purpose of determining individual dumping margin. Individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the exporting country in question can be determined provided the following two conditions are satisfied:
 - (a) that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
 - (b) that the exporter or producer shows that it is not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.
12. It is evident from the above that the intention under Rule 22 is to determine individual dumping margin in respect of an exporter or producer who did not export the subject goods during the period of investigation of the original investigation. Since such producer/exporter did not export subject goods to India during the period of investigation of the original investigation, the Authority could not have determined individual dumping margin in respect of its exports at the time of original investigation. The purpose of new shipper review provision is, therefore, to provide an opportunity to such producer/exporter to claim individual dumping margin considering that these exporters have been granted residual dumping margin during the original investigation.
13. In the instant case, applicants filed an application before the Authority seeking individual dumping margin and requested for initiation of the new shipper review. The basic requirements for initiating the New Shipper Review under Rule 22 are that (a) anti-dumping duty is applicable on the subject goods and (b) the exporters or producers who are seeking determination of individual margin of dumping must not have exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation and they must show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the subject goods.
14. The Authority notes that this review was initiated much before the issuance of trade notice 1/2019 dated 29.01.2019 issued for streamlining the procedure for NSR investigations. It was clearly mentioned in the referred trade notice that it was applicable to NSR applications filed after the date of issue of the said trade notice. Therefore, it is noted that the guidelines/procedure specified in the said trade notice need not be enforced on NSR applications filed prior to the trade notice 1/2019. The Authority however notes that the Applicant though had begun its production of PUC prior to the filing of the new shipper review application.
15. Prior to initiation of new shipper review, the Authority is required to *prima facie* satisfy itself that the conditions of Rule 22 are fulfilled. Unless there is material adverse evidence to contradict the statements made in the application, the initiation of the new shipper review cannot be refused. In the present case, on the date of initiation of new shipper review, there was no material on record to show that the statements made by NSR applicant were not correct. Therefore, it cannot be said that there was no *prima facie* satisfaction on the part of Authority before initiating the new shipper review.
16. In order to examine the eligibility of the applicant as new shipper, the applicant was asked whether (a) the company had, directly or indirectly, exported the product to India during the period of investigation of the original investigation and (b) the applicant or any of its related company had exported the product concerned to India in the period of investigation of the original investigation.

The Applicant provided certification stating that:

- a. The Applicant did not export the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation. Moreover, they got the BIS license to export in December 2016, only i.e. much after the original POI was over;

- b. The Applicant is not related to any exporter or producer in China who had exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation;
 - c. The related companies of the Applicant did not engage in the manufacture of the subject goods;
 - d. The related companies of the Applicant are not related to any exporter or producer in China who had exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation;
17. The Authority considered the submissions of the Domestic Producers in this regard but did not find any adverse material against the Applicant's claim of being a new shipper.
18. During the investigation, the Authority neither found any evidence regarding relationship of the Applicant with any of the exporters or producers in China, who are subjected to anti-dumping duty nor any material evidence in this regard was brought before the Authority by any of the interested parties. The Authority, therefore, notes that the New Shipper Review investigation was initiated as per provisions laid down in Rule 22 of the AD rules which is in conformity with article 9.5 of the WTO AD Agreement.
19. As regards the period of investigation, the Authority is well within its rights to determine a period shorter than 12 months, but longer than 6 months. In the case of a New Shipper, it is not uncommon for a shorter period of time to be considered as the period of investigation. Thus, the selection of the period of investigation is justified.
20. The authority takes note of the fact that the applicant's effort to export PUC during the POI was impeded on account of non-publication of the corrigendum with regard to the correction of the exporter's name in the notification by the Department of Revenue.
21. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of a public file.

F. Methodology for determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Submission relating to Normal Value and Export Price

Submissions made by the Domestic Industry

23. The Domestic Industry has made the following submissions:

- (i) That Normal value for China PR has to be determined in terms of the provisions for non-market economy countries.
- (ii) That since the applicants have not filed additional questionnaire and therefore, they are not entitled for normal value based on their own data.

- (iii) Determination of normal value should be done as per methodology adopted in prescribed format, it is not clear whether the applicant wants the DA to determine normal value ignoring procedure that is followed by the DA.
- (iv) Normal value basis determined by the DA as follows:
 - 1. On basis of price or constructed value in the market economy third country
 - 2. Price from such third country to other countries including India
 - 3. Any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.
- (v) Further, the Rule 22, does not imply that the DA is obliged to give individual dumping margin to these exporters on the basis of their own normal value and own export price.

Submissions by NSR Applicant

- 24. That the Authority should construct the normal value for them as per their standard practice.
- 25. That the Authority should use the export price based on the export quantities of the producer and exporter. It is further submitted that since the name of one of the exporters was not amended in the custom notification no adverse inference can be drawn against applicants because of lack of understanding between two departments of the government.

Examination by the Authority

- 26. The Authority also notes that Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a*

particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

27. Article 15 implies that provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire in 15 years from the date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th December 2016.
28. With regard to the submissions made by the petitioner, it is noted that the commitments under para 15(a) (i) of the Accession Protocol signed by China with WTO requires that the producers under investigation should clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product. In event of this being substantiated, the importing WTO member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability. Further Article 2.2.1.1 of WTO and AD Rules of India requires that the financial records of producer/exporter reasonably reflect the production costs. Therefore, information and supportive evidence thereof in respect of the following is required to be provided.
 - a. Decisions in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labor, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant State interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
 - b. Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
 - c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.
29. As a part of the proceedings in this investigation, the Authority had sent supplementary questionnaire to the applicant seeking the above information. In the absence of any response from the applicant to the said supplementary questionnaire, the Authority has constructed the normal value on the basis of facts available.
30. The constructed normal value is determined as *** USD per MT.

EXPORT PRICE

31. As per the Exporter's Questionnaire, during the POI, the Applicant exported *** MT (*** tyres) of subject goods to India for the net invoice value of *** USD directly to independent customers in India. The Applicant has claimed adjustments for inland freight, port handling expenses, credit cost and bank charges. The Authority has allowed the adjustments as claimed and determined the export price at ex-factory level in respect of the Applicant. Details of the same are mentioned in the dumping margin table appended below.

DUMPING MARGIN

32. Comparing the aforesaid normal value and export price as determined, the individual dumping margin determined for the Applicant during the POI is as follows:

Normal Value	USD/MT	***
Export Price	USD/MT	***
Dumping Margin	USD/MT	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin	Range	0-10

G. POST-DISCLOSURE COMMENTS BY INTERESTED PARTIES

Submissions made by the domestic industry

- i. Authority has issued supplementary questionnaire and in view of non-co-operation thereof the Authority has determined normal value based on facts available. It is surprising that the exporter has also claimed that normal value may be calculated as per facts available. It is not disclosed as to what facts available have been considered. The dumping margin determined for the exporter is 0-10%, which is quite low and thus is likely to cause significant prejudice to the domestic industry in case the same is considered for fixation of ADD. Nor the methodology adopted has been disclosed. The domestic industry is thus handicapped in offering comments on the normal value.

- ii. With regard to existence of related party, despite specific submissions in the oral hearing and written submission thereafter, same have not been considered and not even been recorded in the Disclosure Statement. When the domestic industry has specifically identified some entities, the disclosure statement does not state whether those entities are related to the applicant. Authority is requested to look into the submission made by the domestic industry in this regard and thereafter issue and intimate the interested parties on the essential fact of whether or not there are other related parties and whether or not they exported goods to India.
- iii. It is not clear whether the Authority proposes to consider granting HK Trade Wind Limited trade channel separate duties, if levied.
- iv. During the oral hearing it was argued that the normal value be determined on the basis of the cost of the exporter. Supplementary questionnaire was issued. However, the exporter refrained itself from replying to the same. The exporter must thus be held as a non-cooperative exporter and the investigation should be immediately terminated.
- v. Domestic industry's response to the rejoinder submissions made by the NSR applicant, as noted in the disclosure statement, is as under -
 - a. Applicants had submitted that the BIS license was issued to them in December 2016, and therefore, before that period they could not have exported the subject goods to India. The domestic industry is unable to understand the relevance, importance and significance of such a statement to an anti-dumping proceeding. The applicant however, has not exported even after getting the said BIS license.
 - b. The Applicant stated it did not claim excessive confidentiality. The domestic industry has provided an exhaustive list of the documents claimed confidential by the applicant which are available in public domain. It has prevented the domestic industry from defending its interests.
 - c. As regards the contention by the applicant that Trade Notice No. 08/2018, was issued after the present application and is thus not applicable, the domestic industry states that even if application was filed earlier there was sufficient time to update application and even if trade notice was subsequent to application, the principles of the trade notice still apply.
 - d. The domestic industry claims that the NSR applicant has been trying to misguide the authority by submitting incomplete facts in regard to observation of the Hon'ble High Court of Delhi in H and R Johnson (India) Limited v. Union of India & Ors. [2008 (232) E.L.T. 390].The High Court order being referred is an interim relief order wherein the Court did not go into the merits of the Tribunal's order. The Madras High Court in Saint Gobain vs. Union Of India, Writ Appeal Nos.412 to 414 of 2018 (the most recent case), stated that the findings of Tribunal holds good in H & R Johnson case as the writ petition before the High Court in that case was withdrawn.
 - e. The applicant exporter had started production prior to the filing of present investigation. Thus, it is all the more relevant to consider a retrospective POI. Further, even if it is accepted that a prospective period of investigation is allowed for first-time shipper, it becomes more important to examine the bonafide of the transactions made. In this case after availing the prospective period of investigation the applicant has made just one export consignment throughout the period of investigation, which shows the mala-fide of the applicant.
 - f. The applicant has failed to show that how the requirement of commercial quantity is in violation of Anti-dumping agreement and Rule 22 of the ADD Rules. The requirement of commercial quantities has been embraced by so many WTO members. The DGTR has also incorporated commercial quantities as part of new shipper reviews through Trade Notice No. 08/2018 dated 25th April, 2018. Indian past practice and jurisprudence in NSR applications by other jurisdictions also shows the export transactions by a new shipper ought to be "commercial/ significant quantity".
 - g. The NSR applicant has argued that the requirement of "commercial quantities" as proposed by the Domestic Industry shall encourage the concerned exporters to artificially lower down their prices to absorb the anti-dumping duties. This presumption of the NSR applicant is devoid of any basis in reality. As can be seen in the present case the prices of the applicant is artificially higher than at the prices at which other producers attracting the same duty are able to realize. Secondly, the argument in itself implies that the Designated Authority cannot

conduct new shipper review, as the exporter cannot undertake exports in commercial quantities and the Designated Authority cannot determine export price without exports in commercial quantities. Commercial quantities have to be seen in the light of the nature of the product. It is a moot point whether or not only 260 pieces constitute commercial volumes in a product having a demand in the region of 60-80 lacs pieces and whether Designated Authority can determine dumping margin for such minuscule imports. Thirdly, when so many exporters have exported so significant volumes with duty (including many of them attracting residual duty), can exporter claim existence of duty as a hindrance in undertaking exports. Fourthly, when ADD paid prices are still lower than selling price of the domestic industry, what is preventing the exporter in selling reasonable volumes even after ADD. Thus, it has remained unexplained why and how the NSR applicant has undertaken ceremonial exports at a price higher than other Chinese prices and why a customer in India purchased at such higher price instead of buying from other Chinese suppliers.

- h. The NSR applicant while pleading for grant of individual rate of duty instead of adopting the rate applicable to non-sampled cooperative exporters has quoted WTO panel report in Mexico-Rice case. The argument of the applicant on the basis of WTO Panel report In Mexico –Rice is misplaced since in that panel report the investigation didn't even undertake sampling. The report only provides that absence of any cross-referencing in Article 9.5 of the Agreement shows there is no obligation on Authority to calculate a residual duty margin by giving neutral margin as per Article 9.4. The WTO Panel observation was with regard to obligation on the Authority under a law and that too in an original investigation.

Submissions made by the NSR applicant

- 33. Applicant has submitted that since the Authority has initiated the investigation for chain of M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. (Haohua) (Producer) with Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., (exporter) and H K Trade Wind Trading Limited (exporter), and Customs have provisionally exempted the payment of anti-dumping duties for said chain only, it is necessary to mention the same chain in the notification so that the provisional assessments are also finalized accordingly. The applicant submits that the same chain should therefore be mentioned in the final findings also.

H. Examination of the Authority

- 34. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and have been examined and addressed in the foregoing parts of the present findings and at the time of issue of the disclosure statement. The findings above deal with all such arguments of the domestic industry and the NSR applicant. However, the Authority has examined these submissions herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:
 - a) The authority notes that despite non-issue of corrigendum by the Department of Revenue the producer M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. have always had the option of exporting the subject goods in reasonable quantity through other exporter M/s Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd. The authority notes that the very fact they have chosen to export only minuscule quantity of *** MT through this trader raises the question about the bona-fide.
 - b) The authority notes that the Applicant has exported only a meagre quantity of subject goods to India during the entire period of investigation. Such a minuscule quantum of exports cannot be treated as the reasonable quantity and such export transactions are not representative enough to be taken into account for the purpose of determination of individual margins.

I. Conclusion and Recommendation

- 35. Accordingly, the Authority does not recommend any individual dumping margin for the NSR applicants namely M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. (Haohua) (Producer), Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., (exporter) and H K Trade Wind Trading Limited (exporter).
- 36. The Authority holds that NSR applicants are not entitled to individual dumping margin. The Authority, therefore, recommends that the exports of the subject goods made by M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd. (Haohua) (producer), M/s Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd (exporter) and M/s H K Trade Wind Trading (exporter) from the date of initiation of the present NSR investigation may be subjected to levy of Anti-Dumping Duty as imposed earlier on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR vide Customs Notification No. 45/2017- Customs (ADD) dated 18.9.2017.

J. Further Procedure

37. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority, W.P. (Civil) No. 8202/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General